

## चीन सीमा पर सड़कों पर पैसा खर्च करेगी सरकार

### चर्चा में क्यों?

सूत्रों के मुताबिक, सरकार **वाइब्रेंट वलैज प्रोग्राम (VVP)** के तहत **उत्तराखंड और सिककिम में चीन सीमा पर बनने वाली प्रत्येक किलोमीटर सड़क के लिये 2 करोड़ रुपए** से अधिक खर्च कर सकती है।

### मुख्य बद्दि:

- **केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA)** ने चीन सीमा से लगे क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिये **अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिककिम में VVP** के तहत 113 सड़कों को मंजूरी दी है।
  - अरुणाचल प्रदेश में जहाँ 105 सड़कों को मंजूरी दी गई है, वहीं **उत्तराखंड में पाँच** और सिककिम में तीन सड़कों को भी मंजूरी दी गई है।
- गृह मंत्रालय के मंजूरी-पत्र के अनुसार, **उत्तराखंड के पथौरागढ ज़िले में 119 करोड़ रुपए** की लागत से 43.96 किलोमीटर सड़कें बनाई जानी हैं।
  - प्रत्येक किलोमीटर सड़क पर 2.7 करोड़ रुपए की लागत आने की उम्मीद है। एक बार निर्माण के बाद, "परसिंपत्त" का रखरखाव राज्य सरकार को करना होगा।
  - **सिककिम में, VVP के तहत उत्तरी सिककिम में चुंगथांग और मंगन ब्लॉक में 96 करोड़ रुपए** की लागत से लगभग 18.73 किलोमीटर लंबी सड़कों एवं 350 मीटर स्टील पुलों को मंजूरी दी गई है।
  - प्रत्येक किलोमीटर सड़क निर्माण पर 2.4 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

### वाइब्रेंट वलैज प्रोग्राम

- यह एक **केंद्रीय वित्तपोषण कार्यक्रम** है जिसकी घोषणा **केंद्रीय बजट वर्ष 2022-23** (2025-26 तक) में उत्तर में सीमावर्ती गाँवों को विकसित करने और ऐसे **सीमावर्ती गाँवों के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ की गई**।
- इसमें **हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिककिम और लद्दाख** के सीमावर्ती क्षेत्र शामिल होंगे।
- इसके तहत 2,963 गाँवों को कवर किया जाएगा, जिनमें से 663 को पहले चरण में कवर किया जाएगा
- ग्राम पंचायतों की सहायता से ज़िला प्रशासन द्वारा वाइब्रेंट वलैज एक्शन प्लान बनाए जाएंगे
- **वाइब्रेंट वलैज प्रोग्राम की वजह से 'सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम' के साथ ओवरलैप की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।**